The Government of India has opened this corrosion repairing section at Mancheswar Railway Workshop of Orissa in order to reduce the work load of Kharagpur and Nagpur Railway Workshops. But, it is a matter of regret that the corrosion repairing section of this Railway workshop stopped working from second day of its inauguration. Seven coaches brought from Kharagpur to this place for repairing have also been taken back.

Though interviews were held about a year back to fill up the vacancies in Mancheswar Railway Workshop but none have been given appointment so far. This is another reason for delay of different works which are under the disposal of the corrosion repairing section of Mancheswar Railway Workshop. I, therefore, request the Minister of Railways to pass necessary instructions to fill up those vacancies without any further delay. At the same time, I demand that the Government of India should start the corrosion repairing section at Mancheswar Railway Workshop forthwith.

(ii) NEED FOR INTRODUCTION OF A FAST TRAIN SERVICE BETWEEN LUCKNOW AND ALLAHABAD.

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा शिक्षा में महत्व है। राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इलाहबाद में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है जो इलाहाबाद से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। किन्तु इलाहाबाद एवं लखनऊ के बीच कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जिससे हजारों लोगों को, जिन्हें अपने व्यक्तिगत अथवा राजकीय कार्यों से लखनऊ से इलाहाबाद या इलाहाबाद से लखनऊ जाना पड़ता है, 8 घंटे से 12 घंटा ट्रेन से यात्रा में लगता है। एक त्रिवेणी एक्सप्रेस लखनऊ से इलाहाबाद होते हुए चुर्क जाती है तथा चुर्क से इलाहाबाद होते हुए लखनऊ जाती है, की स्पीड कम होने तथा स्टापेज ज्यादा होने से एक्सप्रेस न हो करके पैसेन्जर ट्रेन हो गई है। इसे देखते हुए इलाहाबाद से लखनऊ के लिये एक फास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाये। यदि यह सम्भव न हो तो त्रिवेणी एक्सप्रेस में ही सुधार किया जाये।

(iii) STEPS TO CHECK INDISCRIMINATE CUTTING OF TREES CHITTORGARH DISTRICT OF RAJASTHAN.

प्रो० निर्मल कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वन राष्ट्रीय सम्पदा है। वन अधिनियम, 1980 के अनुसार वन हटाने के लिये भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान चितौड़गढ़, जिले में रावतभाटा, जहां राणा प्रताप सागर डैम है, बेरहमी से जंगल काटे जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 22-9-80 को एक ठेकेदार को डैम में डूब की लकड़ी को निकालने का ठेका नियमों का उल्लंघन करते हुए 7 वर्ष के लिये दिया। यह ठेकेदार डूब की लकड़ी को न निकाल कर आस-पास के हरे-भरे जंगलों को फुर्ती से साफ कर रहा है। कोयले बनाकर प्रतिदिन 8 या 10 टन बेच रहा है। इस व्यक्ति ने भैंसरोडगढ़, पानरवा, जागीर (उदयपुर), बांसवाड़ा, डूंगरपुर (भीलवाड़ा) के जंगलों को साफ किया। इस प्रकार देश की करोड़ों रुपए की वन सम्पदा प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। एक वर्ष में यह स्थिति है तो 7 वर्ष में कितना जगल साफ होगा? अतः मैं केन्द्रीय वन विभाग से आग्रह करूंगी कि अविलम्ब इसमें हस्तक्षेप करके इस अमानवीय, अप्राकृतिक कार्यवाही, जो उक्त ठेकेदार द्वारा की जा रही है, उसको रोके वरना हरे-भरे सभी राजस्थान के जंगल साफ हो गए, जो बचे हुए हैं वह भी साफ हो जायेंगे। फिर भीषण अकाल और अकाल के अलावा वहां के निवासियों के पास क्या बचेगा? केन्द्रीय सरकार इस समस्या को गम्भीर मानते हुए इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।